लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 1- 15 दिसंबर, 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक - 79

"सत्य बोलने का फायदा है कि यह याद रखने की जरुरत नहीं पड़ती कि कब और किसको क्या कहा था।"
: रॉबर्ट बेन्स

प्रगति मैदान में छाया म्हारा हरियाणा 3

पैरा एशियाई खेलों में हरियाणवियों का धाकड़ प्रदर्शन 7

क्राफ्ट व लोक संस्कृति का अनूठा संगम 8

रोकना होगा प्रदूषण

हरियाणा के प्रयासों से सबक ले पंजाब: सुप्रीम कोर्ट

विशेष प्रतिनिधि

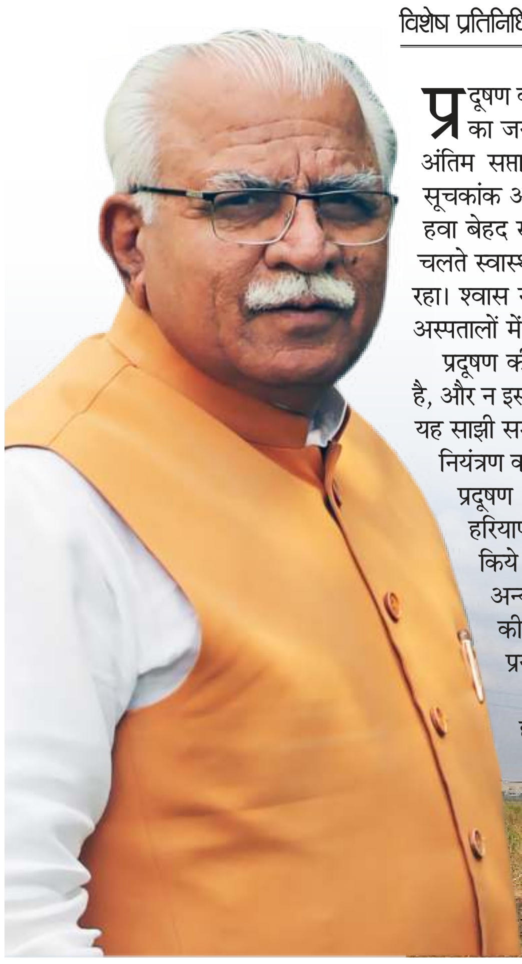

प्रदूषण की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जन जीवन हलकान है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक औसतन 400 रहा। इस श्रेणी की हवा बेहद खराब मानी जाती है। प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उछाल रहा। श्वास रोग व आंखों में जलन के केस अस्पतालों में खूब देखे गए।

प्रदूषण की वजह केवल एक कारक नहीं है, और न इसके लिए एक प्रदेश जिम्मेवार है। यह साझी समस्या है, इस पर गंभीर चिंतन व नियंत्रण की जरुरत है। काबिलेजिक्र है कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की दिशा में हरियाणा सरकार द्वारा सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब व अन्य पड़ौसी राज्यों की ओर से धान की पराली प्रबंधन पर नाकाफी प्रयास हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार के प्रयासों को सराहा और पड़ौसी प्रदेशों को सबक लेने की बात कही। कोर्ट की ओर से पंजाब सरकार को कहा गया कि वह हरियाणा सरकार के प्रयासों का अनुकरण करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के किसानों को श्रेय दिया है।

हरियाणा सरकार की पहल

- वर्ष 2018 से अब तक 6794 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए तथा किसानों को 80071 फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण उपलब्ध कराए गए।
- उपकरणों पर कस्टम हायरिंग सेंटर को 50 प्रतिशत तथा व्यक्तिगत किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान। राज्य के किसानों को अब तक 685 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जा चुके हैं।
- मशीनों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा एक हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान
- मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान क्षेत्र में अन्य फसल बोने पर सात हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान। योजना के तहत एक लाख से अधिक किसानों को 110 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई।
- पराली की खरीद हेतु 2500 रुपए प्रति टन की दर निर्धारित। प्रदेश में 250000 एकड़ भूमि में फसल अवशेष प्रबंधन हेतु पूसा डिक कंपोजर किट किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई।
- कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद व जींद में बायोमास परियोजनाएं सुचारू रूप से क्रियान्वित, जिनमें 30 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रही है। जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए पानीपत रिफाइनरी में एथेनॉल प्लांट।
- पराली से बिजली बनाने का प्लांट करनाल में लगाया जाएगा। भारत सरकार के गैर-परम्परागत ऊर्जा विभाग की ओर से इस तरह का प्लांट लगाने के लिए करनाल को चुना गया है।

कोविड महामारी के दौरान दर्ज केस वापिस लेगी सरकार

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को वापिस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 8275 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कुल 14,127 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वाधिक 1030 एफआईआर गुरुग्राम जिले में दर्ज की गई थी। झज्जर में 814, फरीदाबाद में 765, करनाल में 545 और रोहतक में 646 एफआईआर दर्ज की गई थी।

पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेंगी नियुक्तियां

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में खेल से संबंधित रिक्त पदों पर प्रतिभावान पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्त जायेगा। हमारे खिलाड़ी लगातार विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और खेल विभाग द्वारा नीति अनुसार उन्हें नियुक्ति दी जा रही है। ऐसे सभी होनहार खिलाड़ियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के अनुरूप उपलब्ध पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की भी व्यापक समीक्षा की और अधिकारियों को उनके समाधान में तेजी लाने का निर्देश दिया।

ब्रह्मसरोवर पर सजेगा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव

'गीता' ऐसा अलौकिक प्रकाश पुंज है, जो काल, देश और सीमाओं से परे है। यह सर्वकालिक, सार्वभौमिक और चिरस्थायी है। गीता के इस ज्ञान को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य पूरे विश्व में श्रीमद्भगवद् गीता के शांति, सद्भाव और भाईचारे के संदेश को फैलाना है। वर्ष 2016 के बाद से अब तक मॉरीशस, लंदन, कनाडा और आस्ट्रेलिया में अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजनीति से ऊपर उठकर विश्व को कर्म का सिद्धांत देने वाली गीता की धरती धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद व पानीपत जिलों में पड़ने वाले लगभग 134 तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराने की एक नई पहल की है। इसके तहत 48 कोस में आने वाले महाभारत, रामायण व वामन पुराण में वर्णित तीर्थ स्थलों के प्राचीन, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिगत इनका जीर्णोद्धार कर और भव्य बनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान आगंतुकों को इन 48 कोस के तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाती है, ताकि वे हरियाणा की समृद्ध व आध्यात्मिक संस्कृति से परिचित हो सकें।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने पिछले 9 सालों में भौतिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक व पौराणिक धरोहर को संजोने का काम किया है और इसी दिशा में हरियाणा निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि हरियाणा की महान संस्कृति के जीवन मूल्य नई व युवा पीढ़ी तक पहुंचे और युवा पीढ़ी गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं।

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव ब्रह्मसरोवर पर 7 दिसम्बर से लेकर 24 दिसम्बर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 17 से 24 दिसम्बर तक आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष मुख्य सांस्कृतिक कार्य मों के लिए ब्रह्मसरोवर पुरुषोतमपुरा बाग में मुख्य पांडाल सजाया जाएगा। महोत्सव के मुख्य कार्य म आठ दिन के होंगे और महोत्सव में शिल्प और सरस मेले का आयोजन होगा। इस वर्ष असम राज्य महोत्सव में पार्टर राज्य के रूप में अपनी भूमिका अदा करेगा।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विशेष सहयोग से हरियाणा पैवेलियन आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं जनसंपर्क विभाग की राज्यस्तरीय प्रदर्शनी, हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार, 18 हजार बच्चों का वैश्विक गीता पाठ, गीता रन, शैक्षणिक गतिविधियों, महाआरती, दीपदान, गीता शोभायात्रा, पुस्तक मेला, संत सम्मेलन, फूड फेस्टिवल, जीओआई टैग प्रदर्शनी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा प्रदर्शनी, ऑनलाइन गीता ि ज के साथ-साथ स्कूली विद्यार्थियों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा।

- संवाद ब्यूरो

संपादकीय

रोल मॉडल बना 'कौशल विकास विश्वविद्यालय'

हरियाणा का श्रीविश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अब देश के अन्य प्रदेशों व कुछ विदेशी संस्थानों के लिए भी रोल मॉडल बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गत दिवस इसमें तक्षशिला-प्रशासनिक भवन का 90 ब्लॉक का लोकार्पण किया है। इनमें छह शैक्षणिक ब्लॉक में 69 क्लास रूम हैं और अधिकतर स्मार्ट क्लास रूम, कम्प्यूटर लैब, प्रशासनिक भवन, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है।

सीएनसी लैब, सोलर लैब, एडवांस्ड इलैक्ट्रिक लैब, इलेक्ट्रॉनिक लैब, वेल्डिंग लैब भी उद्घाटन में शामिल हैं। छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास भी परिसर में बनकर तैयार है जिनमें 500-500 बेड की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री के आदेशानुसार इस कौशल विश्वविद्यालय में तीन दर्जन से अधिक कोर्स चल रहे हैं जो युवाओं के कौशल विकास में अहम माने जाते हैं। विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुरूप प्रदेश लेकर अपने कौशल के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में देश का पहला इनोवेटिव स्किल स्कूल बनाया गया है जिसमें एआई, आईटी, ऑटोमेशन, डेटा साइंस, हेल्थ केयर और योग जैसे विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है।

इस विश्वविद्यालय की बेहतर प्लेसमेंट भी हो रही है और युवा यहां से कौशल विकास से आत्मनिर्भर होकर स्वरोज़गार भी अपना रहे हैं।

विश्वविद्यालय के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार की ओर से मंजूर किया गया है जिसमें अब तक 357 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो चुके हैं और जल्द ही सरकार की ओर से विश्व विद्यालय प्रबंधन के अनुरोध पर 150 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी कर दी जाएगी।

-डा. चंद्र त्रिखा

विकसित भारत संकल्प यात्रा

योजनाओं की हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे अधिकारी

केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से हरियाणा विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारम्भ हो चुकी है। यात्रा का लक्ष्य पीएम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, जन धन योजना और स्वच्छ भारत मिशन सहित प्रमुख सरकारी योजनाओं की व्यापक स्तर पर जानकारी एवं लाभ सुनिश्चित करना है।

यात्रा 22 नवंबर से शुरू हो कर अगले 60 दिनों तक पूरे हरियाणा के सभी गांवों को कवर करेगी। राज्य के हर कोने तक पहुंचने तथा जनता से जुड़ने के लिए 72 एलईडी वैन तैनात की गई हैं। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो यात्रा की गतिविधियों के लिए समन्वयक रहेगा।

सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को प्रभावी ढंग से प्रचारित करने के लिए वैन में प्रचार सामग्री, फिल्मों और डिजिटल डिस्प्ले की व्यवस्था की गई है। यात्रा के दौरान महकमों के प्रमुख अधिकारी साथ रहेंगे ताकि पेंशन, आधार, परिवार पहचान पत्र, कृषि और बागवानी से संबंधित योजनाओं की मौके पर जानकारी दी सके।

सार्वजनिक स्थलों पर स्टालों के अलावा, प्राथमिक चिकित्सा के अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने व प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक गांव और वार्ड में स्थित विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तथा विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं डीआईपीआर के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि संकल्प यात्रा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें सभी जिलों के उपयोगकर्ता लॉगिन कर हर कार्य' म एवं गतिविधियों की फोटो व वीडियो अपलोड करेंगें। अतिरिक्त जिला उपायुक्त अपने-अपने जिलों में विकास भारत संकल्प यात्रा की निगरानी और सुविधा के लिए नोडल अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

-संवाद ब्यूरो

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक मानदेय

बचपन को संभालने वाली और तराशने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बच्चों को संस्कारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बड़ी सौगात देते हुए मासिक मानदेय में बढ़ोतरी, सेवानिवृति पर मिलने वाली राशि में वृद्धि करने सहित कई घोषणाएं की।

उन्होंने दस वर्ष से अधिक अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक 12,661 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की। इसके साथ ही, 10 वर्ष तक के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक 11,401 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए प्रतिमाह तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक 6,78 1 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए किया गया है। इस घोषणा के साथ ही हरियाणा देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य बन गया है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 23,486 आंगनवाड़ी वर्कर्स, 489 मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स व 21,732 आंगनवाड़ी हेल्पर्स कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्ति पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की भी घोषणा की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रति वर्ष दो वर्दी के लिए दी जाने वाली राशि 800 रुपए को बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिवर्ष करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यवेक्षक के पद के लिए आवश्यक पात्रता और न्यूनतम योग्यता के आधार पर दस साल के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पर्यवेक्षकों के 25 प्रतिशत पद अलग रखे जाएंगे। पदोन्नति सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा फरवरी, 2024 में आयोजित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में 60 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। उक्त राशि के बाद बढ़ाया गया सारा मानदेय हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

उन्होंने कहा कि हर शिशु के पालन पोषण करने का ज़िम्मा आप सबने अपने कंधों पर उठाया है, यह बहुत सराहनीय कार्य है। बचपन से ही बच्चों को स्वच्छता के प्रति ज़ागरूक रखना, यह भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है।

- संवाद ब्यूरो

जीरो ड्रॉप-आउट राज्य बनाने का अभियान

मनोहर सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब सरकार ने हरियाणा को जीरो ड्रॉप-आउट राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पीपीपी डाटा में दर्ज 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को ट्रैक करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यदि कोई बच्चा किसी सरकारी या निजी स्कूल, गुरुकुल, मदरसे या कदम स्कूल इत्यादि में नामांकित नहीं है, तो उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा सकें।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हर बच्चा स्कूली शिक्षा ग्रहण करे, यही सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। बच्चे अच्छे नागरिक बनें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। इसके लिए बच्चों और शिक्षक का अनुपात सही होना चाहिए। वर्तमान सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ हर प्रकार से उनकी चिंता कर रही है, ताकि उनकी नींव मजबूत बन सके। गांव से 1 किलोमीटर की दूरी से अधिक पर स्थित स्कूलों में आने-जाने के लिए सरकार की ओर से बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

हरियाणा सरकार ने डॉ ऊषा गुप्ता को 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान का सलाहकार नियुक्त किया है, जो प्रदेश में सम्बंधित अभियानों का मार्गदर्शन करेंगी। डॉ गुप्ता स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत हुई हैं।

विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2021-22 में 'विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना' लागू की गई है।

प्रगति मैदान में छाया म्हारा हरियाणा

विशेष प्रतिनिधि

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 'वसुधैव कुटुंबकम- व्यापार से एकजुटता' विषय पर आधारित हरियाणा पेवेलियन आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। हरियाणा पवेलियन में राज्य की परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और उपलब्धियों के साथ आधुनिक तकनीक के सहारे प्रगति के पथ पर अग्रसर प्रदेश को दिखाया गया है। पेवेलियन में व्यापार और वाणिज्य से लेकर खेल तथा श्रीमद्भागवत गीता में निहित 'कर्म' के संदेश का समावेश देखने को मिला।

ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ हरियाणा के माध्यम से प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर, 2023 तक लगे भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में बनाए गए हरियाणा पवेलियन में प्रदेश की परंपरा के साथ आधुनिकता के सफ़र को प्रदर्शित किया गया। हरियाणा मंडप को ऐसे अनूठे ढंग से आकार दिया गया जहां प्रदेश की समृद्ध संस्कृति व परंपरा के दर्शन हो सकें।

संस्कृति व परंपरा का प्रदर्शन

हरियाणा मंडप में सबसे पहले हरियाणवी संस्कृति व परंपरा की झलक देखने को मिली। पिछले नौ वर्षों के दौरान हरियाणा में आई डिज़िटल और औद्योगिक क्रांति को भी पेवेलियन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। स्टार्टअप की झलक भी विभिन्न उत्पादों के रूप में देखने को मिली। इस बार हरियाणा पवेलियन में कुल 51 स्टॉल लगाए गए। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्टार्टअप के रूप में आए बदलाव को पेवेलियन में दिखाने का मौका युवाओं को दिया गया। एक ओर जहां नवाचार से अग्रणी राज्य के रूप में हरियाणा आगे बढ़ते दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर मंडप में पारंपरिक लोकाचार का भी समावेश दर्शाया गया। निकास द्वार को गुरुग्राम के आधुनिक क्षितिज के रूप में डिजाइन किया गया था, जो हरियाणा को एक आधुनिक राज्य के रूप में उजागर करता है। अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम उपलब्धियों को प्रदर्शित करते बिंदू भी दिखाई दिये।

पृष्ठभूमि की झलक

हरियाणा मंडप में वैदिक युग व पुराने समय की संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया। पूर्व में उत्सव के अवसर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री को विरासत के रूप में पंडाल में जगह मिली। ऐतिहासिक राखीगढ़ी (हिसार) में मिले सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को कलाकृति के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। यहां विशेष रूप से कारीगर गैलरी व मिट्टी से बनी वस्तुओं के अलावा दो स्थानों पर लाईव डेमो के लिए प्लेटफार्म भी दिए गए थे। मंडप के एक हिस्से में गांव की चौपाल में पेड़ के नीचे समूह में बैठकर पंच परमेश्वर अपने गांव के विकास को लेकर अहम फैसले लेते दिखाई देते हैं जिससे ग्रामीण पृष्ठभूमि की झलक मिलती है तो दूसरी ओर खेलों में हरियाणा के प्रदर्शन को रेखांकित किया गया था।

औद्योगिक प्रगति

नौ वर्षों के दौरान हरियाणा ने औद्योगिक प्रगति में एक लम्बी छलांग लगाई है। प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह से लेकर उद्योग के लिए मदद की विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के फलस्वरूप ही हरियाणा मंडप में कई नए स्टार्टअप दिखाई दिए हैं जो ग्रामीण स्तर पर छोटी इकाई से शुरू होकर आगे बढ़े हैं।

हरियाणा समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत रखता है, आधुनिक समय में यह ऑटोमोबाइल क्षेत्र के रूप में उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया है। इतना ही नहीं, बदलते समय के साथ तालमेल बिठाते हुए इसने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी अपना लिया है, जिससे बेंगलुरु के बाद गुरुग्राम देश की दूसरी 'सिलिकॉन वैली' बन गई है।

ग्रामीण

औद्योगिक क्रान्ति का परिचायक बनता हरियाणा

हरियाणा पवेलियन को देखते ही उस संस्कृति की यादें ताजा हो आई जहां सिंधु घाटी और सरस्वती सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक हरियाणा में व्यापार के सफ़र को दर्शाया गया।

भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती एर्विन मंजुल कहती हैं कि राखीगढ़ी व अन्य स्थानों पर मिले पुरातन अवशेष व शिलालेख से लगता है कि हरियाणा के लोग व्यापार में हजारों वर्ष पहले से आगे रहे होंगे। राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान सामने आया कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में यहां भट्ट्यों में आभूषण तैयार होते थे और आभूषण तैयार करने की तकनीक भी काफी समृद्ध मानी गई है। यहां मिले तांबे की अगुंठियां, चूड़िया व सामान से अनुमान लगाया गया है कि तब यहाँ से व्यापार मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान व दुनियां के अन्य देशों तक फैला हुआ था।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मौजूदा राज्य सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पिछले नौ वर्षो के दौरान नई नीतियों को लागू किया है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा औद्योगिक व रोजगार नीति लागू की गई है। ट्रेड फेयर अथॉरिटी हरियाणा की प्रशासक सुश्री सोफिया दाहिया ने बताया कि इस बार हरियाणा पवेलियन में कई नए स्टार्टअप के सहारे बढ रहे निवेश को भी दर्शाया गया जिसमें बताया गया कि नया उद्योग लगाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की मदद व रियायतें दे रही है।

हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2023- 24 में 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर (11.2 लाख करोड़) रहने की संभावना है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला में 886 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है। इसे दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जोड़कर बनाया जा रहा है ताकि उस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले और वहाँ विकास को गति मिले। इसी तरह कई बड़े प्रोजक्ट भी प्रदेश के कई हिस्सों में चल रहे है। निवेश के लिए प्रदेश सरकार की नीतियां व्यापार हितेषी ढ़ंग से तैयार की गई है। यहां तक की विदेशी निवेशकों के लिए हरियाणा पहली पंसद बन रहा है।

एक जिला-एक प्रोडेक्ट का संकल्प

प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले को व्यापार व उद्योग के मामले में आगे बढ़ाने के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' नीति को लागू किया हुआ है जिसका उद्देश्य उस जिले में बड़े स्तर पर उत्पादित/पैदावार होने वाली वस्तु को अलग पहचान दिलाने का है। अलग-अलग जिलों में अलग अलग उत्पाद को इस नीति के तहत लिया गया है ताकि वहां उसी उत्पाद से संबंधित प्रोडेक्ट को बड़े स्तर पर तैयार किया जा सके और मार्केटिंग की समस्या का भी समाधान हो। सरकार की इसी नीति के उत्साहजनक परिणाम आए और हरियाणा पवेलियन में इसे विशेष रूप से उल्लेखित किया हुआ है।

कैथल में महर्षि वाल्मिकी संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए बस खरीदने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने स्वैच्छिक कोष से 25 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है।

हरियाणा में 239 महिला हैल्प डेस्क, 33 महिला थाने, 81 महिला पीसीआर तथा स्कूटी राइडर्स, 24 कंपनियां तथा 46 पैट्रोलिंग व्हीकल 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा में तैनात की गई हैं।

गांवों में होने लगा

मनोहर सरकार ने ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस किया है, जिसका परिणाम ग्रामीण अंचल में साफ दिखाई दे रहा है। ग्राम विकास के माध्यम से ही स्वराज की अवधारणा को साकार किया जा सकता है, इस समावेशी लक्ष्य के साथ राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

मनोज प्रभाकर

'ग्राम्य विकास के बिना स्वराज की कल्पना नहीं की जा सकती।' मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार शुरू से ही महात्मा गांधी के उक्त मूलमंत्र के साथ कार्य कर रही है। इस पथ पर चलते हुए प्रदेश में पिछले करीब नौ साल में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इससे न केवल गांवों की तस्वीर बदली है बल्कि शहरों जैसी सुविधाएं भी मिलने लगी हैं।

बिजली पानी सड़क । 24 घंटे बिजली, हर घर नल से जल, पक्की सड़कें व गलियां, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, बैंकों व अन्य प्रतिष्ठानों में ऑनलाइन होते कार्य इप सबसे ग्रामीण परिवेश का माहौल बदला है। शहरी तर्ज पर बनते सुंदर मकान, तालाबों के किनारे बनते पार्क, छोटी-छोटी दुकानों से सजते मिनी बाजार, शिक्षित पीढ़ी का रुतबा, बोलचाल व पहनावा, शहरीकरण से होड़ लगाती रहन सहन की संस्कृति, साफ सफाई और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते लोग, इन सबसे यही लगता है जैसे गांव तेजी से कस्बा और कस्बे शहर होने की राह पर हैं।

लाल डोरा खत्म करने के लिए आरंभ की गई स्वामित्व योजना लोगों को खूब रास आई है। जिन मकानों में लोग वर्षों से रह रहे थे और उन मकानों के मालिक नहीं बन पाए थे,

वे इस योजना के तहत मालिक बन गए हैं। मनोहर सरकार ने उनको 80 रुपये में रजिस्ट्री देकर मकानों का मालिक बना दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना की परिकल्पना की थी तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना को पूरे देश में लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा के 6260 गांवों में लाल डोरे के भीतर 25.17 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बनाये जा चुके हैं।

ग्राम पंचायतों को सशक्त किया:

गांवों को विकसित करने और विकास कार्यों में तेजी लाने हेतु मुख्यमंत्री ने शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने का निर्णय लिया है। आंचल के गतिशील विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करते हुए उन्हें स्वायत्ता प्रदान की ताकि वे अपने स्तर पर खुलकर विकास कार्य करवा सकें। पंचायतों को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई। गरीब तबके की भागीदारी को बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग-ए को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अंतर जिला परिषद का गठन कर पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद को विभिन्न प्रकार के छोटे विकास कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

ग्राम सचिवालय:

ई-गवर्नेंस की अवधारणा को मुख्यालय व जिला सचिवालयों में लागू करने के बाद गांवों में ग्राम सचिवालय स्थापित करने की पहल की गई है। अब तक 1856 ग्राम सचिवालय खोले जा चुके हैं, शेष की प्रि`या जारी है। इन ग्राम सचिवालयों में पटवारी, पंचायत सचिव, सरपंच इत्यादि के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, इनमें अटल सेवा केंद्र भी खोले गए हैं, ताकि गांवों के लोग सरकार की ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ एक ही छत के नीचे प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री की इस सोच की ग्रामीण खुले मन से प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्हें तहसील व जिला मुख्यालयों के कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है।

जनप्रतिनिधियों का सम्मान:

छोटी सरकारों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का प्रतिदिन विधायक, सांसदों व मंत्रियों की तरह जनता से मिलना होता है और कभी-कभी आयोजन भी अपने स्तर पर करना होता है। प्रतिदिन की इस खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री ने पंच से लेकर जिला परिषद के अध्यक्षों के मासिक मानदेय में अभूतपूर्व

आईआईएम रोहतक द्वारा गुरुग्राम में एक विस्तार परिसर स्थापित किया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि यह पहल शैक्षिक अवसरों को बढ़ाएगी तथा आर्थिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

मुख्यमंत्री ने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने पर केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है।

शहरों सा अहसास

वृद्धि की है। इनके अलावा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय 15,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। चौकीदारों का 11,000 रुपये तथा नम्बरदारों का मासिक मानदेय 3,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भी 357 रुपये प्रतिदिन की गई है।

स्वास्थ्य सेवाएं:

ग्रामीण जीवन के बारे में आम तौर पर कहा जाता है कि वहां पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं होती। मनोहर सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया है। गांव के सब सेंटर से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक चिकित्सा सेवाओं को सहज व सुलभ किया गया है। मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां की गई हैं तथा तमाम आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। यह बात और है कि मरीजों को शहर के अस्पतालों की ओर

भागने की आदत बनी है। गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान योजना व चिरायु योजना के तहत निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, मरीजों को सात आवश्यक सेवाएं मुफ्त प्रदान करती है, जिसमें सर्जरी, प्रयोगशाला परीक्षण, नैदानिक सेवाएं आदि शामिल हैं।

मेडिकल कालेज :

स्वास्थ्य सेवाओं की सहज उपलब्धता के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की ओर तेजी से कार्य हो रहा है। अक्टूबर, 2023 में कैथल जिले में 950 करोड़ रुपये की लागत से भगवान परशुराम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। 20 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस चिकित्सा संस्थान की लागत करीब 950 करोड़ रुपये होगी, इसमें 100 एमबीबीएस सीटें और 500 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा।

गौरतलब है कि 2014 से पहले राज्य में छह मेडिकल कॉलेज थे, जिनमें कुल 700 एमबीबीएस सीटें थीं। वहीं आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 2,185 एमबीबीएस सीटें हैं। फतेहाबाद, सिरसा, चरखी दादरी और पलवल सहित विभिन्न शहरों में आठ अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है।

शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तनः

मनोहर सरकार में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया जिसके चलते अभिभावकों में यह धारणा बन गई कि प्राइवेट स्कूलों की तुलना में राजकीय स्कूलों की पढ़ाई अव्वल है। यह सही भी है। पिछले सात- आठ वर्षों के रिकॉर्ड पर गौर किया जाए तो ऐसा ही है। परिणाम बेहतर रहे हैं। एक समय था जब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाना बहुत कम हो गया था लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। स्कूलों में विभिन्न योजनाओं के तहत छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। छात्राओं के लिए तो कालेज स्तर पर निशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा गरीब परिवार के बच्चों को प्रति वर्ष वजीफा भी दिया जा रहा है। स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनने से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हरियाणा के विद्यार्थियों की प्रतिभा साफ देखी जा रही है।

राजकीय क्षेत्र में 56 विश्वविद्यालय और 182 कॉलेज हैं, जिनमें से 63 महिला शिक्षा के लिए समर्पित हैं। सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक तक की छात्राओं के लिए ट्यूशन फीस में पूरी छूट है। राज्य भर में 137 से अधिक नए सीबीएसई से संबद्ध सरकारी मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक संस्कृति विद्यालय खोले गए हैं, जबकि ब्लॉक स्तर पर 1,418 संस्कृति प्राथमिक विद्यालय शुरू किए गए हैं।

ई-अधिगम योजना के तहत दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 जीबी मुफ्त डेटा वाले 5.5 लाख से अधिक टैबलेट प्रदान किए गए हैं।

सुपर-100 कार्यक्रम के तहत, सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि सुपर-एनडीए छात्रों को एसएसबी परीक्षाओं को पास करने के लिए उच्च स्तरीय कोचिंग और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

गांव पर्यटन

हरियाणा अब धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के साथ-साथ साहसिक खेलों का उपयोग करके देश के भीतर और बाहर से घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की बड़ी योजना लेकर आया है। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। होम स्टे व पर्वतीय क्षेत्र की योजनाएं काफी सराही जा रही हैं। राज्य सरकार ऐतिहासिक तथ्यों और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ अंबाला और अन्य स्थानों के नायकों द्वारा निभाई गई भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए अंबाला में एक युद्ध स्मारक स्थापित कर रही है।

गांवों में सफाई व्यवस्था व जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ सामुदायिक केंद्र और पार्क एवं व्यायामशालाओं की स्थापना कर ग्राम्य जीवन की रूपरेखा में नया बदलाव आया है।

ग्रामीण विकास को रफ्तार देंगे हाइवे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए रेलवे और सड़कों व अन्य बुनियादी ढांचों को निरंतर मजबूत किया जा रहा है ताकि भविष्य में प्रगति की राह में कोई बाधा न आए। अपनी सोच को वित्तीय ताकत देते हुए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2023-24 के बजट में सड़कों व पुलों के लिए 3,936 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग से हरियाणा सड़कों का जाल बुनने में सफल हुआ है। राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़कें पूरे राज्य में फैली हुई हैं। जहां हर गांव में सड़क है, वहीं हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। अंबाला-कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण 10,646 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है। कुंडली-मानेसर-पलवल-गाजियाबाद-कुंडली एक्सप्रेसवे खोल दिया गया है और इस पर यातायात जारी है।

एयरोसिटी दिल्ली, धारूहेड़ा और पानीपत से दिल्ली के बीच एक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कनेक्टिविटी परियोजना प्रस्तावित की गई है, और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (पलवल से खरखौदा) निर्माणाधीन है। इस पर 5,618 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

प्रदेश में जहां 19,664 करोड़ रुपये की लागत से 32,915 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत की गई है, वहीं 2,135 करोड़ रुपये की लागत से 2,213 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण भी किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि नाबार्ड के तहत 3,969.51 किलोमीटर लंबी 405 सड़कों का काम अनुमानित 2,240.61 करोड़ रुपये के बजाय 1,760.65 करोड़ रुपये की लागत पर पूरा किया गया है।

इनके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तृतीय चरण के अंतर्गत 9,29.57 करोड़ रुपये की लागत से 2,109 किमी लंबाई की सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष 387 किमी मार्ग पर कार्य प्रगति पर है।

पंचकूला की शिवालिक पहाडियों में गांव नीबवाला से हिमाचल को जोडने़ वाला पुल तैयार, आवाजाही शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर हरियाणा सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश का समग्र विकास करा रही है। अंत्योदय की भावना का अनुसरण करते हुए सबके विकास का ध्यान रखा जा रहा है। अथक परिश्रम के चलते शासन प्रशासन में पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता बरती जा रही है जिसका परिणाम यह है कि निवेश के मामले में हरियाणा निवेशकर्ताओं के लिए सबसे पसंदीदा क्षेत्र बन गया है।

- मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा

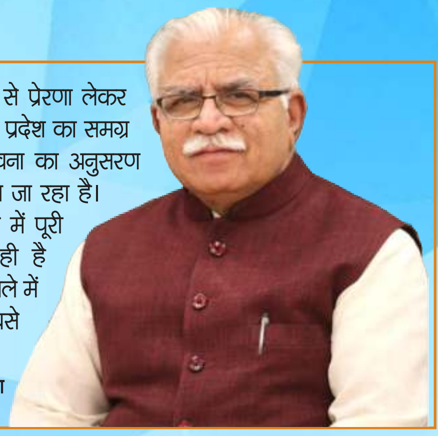

सद्भावना एवं भाईचारे का प्रतीक कपाल मोचन

हरियाणा के प्राचीन सिन्धुवन क्षेत्र बिलासपुर में स्थित इस पवित्र स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक राज्य स्तरीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें उत्तर भारत के अनेक राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ इत्यादि से लाखों की संख्या में भिन्न-भिन्न धर्मो के श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस वर्ष तीर्थ राज कपाल मोचन में श्री कपाल मोचन-श्री आदि बद्री मेले का आयोजन 23 नवम्बर से 27 नवम्बर तक किया गया।

प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की लागत से एथनॉल प्लांट लगाएगी। चीनी मिलों में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करना भी प्रस्तावित है।

आधार कार्ड को निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा अपडेशन करने की तिथि बढ़ाकर 14 दिसंबर 2023 कर दी गई है।

हरियाणा के विकास में पूर्वांचलवासियों का विशेष योगदान

छठ पूजा महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छठ पर्व पर पूर्वांचलवासियों को महत्वपूर्ण सौगात देते हुए पानीपत जिले में छठ पूजा के लिए समर्पित तीन घाटों के निर्माण की घोषणा की। इनके निर्माण पर 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा हेतु साफ पानी के लिए अवलाना डिस्ट्रीब्यूटरी पर 2 करोड़ रुपए की लागत से 700 फीट के घाट, असंध रोड पर थर्मल चैनल के पास एक करोड़ रुपए की लागत से 300 फीट के घाट और बाबरपुर पुल के पास ड्रेन नंबर 2 पर 2 करोड़ रुपए के साथ 300 फीट का एक अन्य घाट का निर्माण किया जाएगा।

श्री मनोहर लाल ने महराना गांव की भूमि पर दो नहरों के बीच सूर्य मंदिर के निर्माण की भी घोषणा की। इस उद्देश्य के लिए गांव की जमीन के हस्तांतरण का कार्य प्रर्क्रियाधीन है। मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य के लिए भूमि के सफल हस्तांतरण के बाद बनने वाले सूर्य मंदिर के लिए 21 लाख रुपए के स्वैच्छिक अनुदान की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस पावन अवसर पर माताओं, बहनों और बेटियों सहित प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी को छठ पूजा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई दी।

उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्वांचल के सभी भाइयों और बहनों की हरियाणा के विकास में उनके अटूट योगदान के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि आपका परिश्रम और विशेषज्ञता राज्य में उद्योगों को बनाए रखने और कृषि विकास को बढ़ावा देने में सहायक रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद, आप राज्य में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में योगदान देने के लिए दिन-रात अथक परिश्रम करते हैं।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में लगभग 1000 कॉलोनियों को नियमित किया है। इन कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का निवेश रखा गया है।

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हरियाणा राज्य में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों की मांगों को पिछली सरकारों में नजरअंदाज कर दिया जाता था। आज तक किसी भी सरकार ने आपकी चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने स्थानीय लोगों के केवल अनुरोध मात्र पर ही तीन घाटों और सूर्य मंदिर को मंजूरी देकर जरूरतों को पूरा किया है। इतना ही नहीं अन्य तमाम पहलूओं पर उनका ध्यान रखा जा रहा है।

वह तो झांसी की झलकारी थी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में निरंतर समाज के संत महापुरुषों और वीर वीरांगनाओं की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने की दिशा में शुरू की गई संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत पलवल में रानी लक्ष्मी बाई की सेनापति रही झलकारी बाई की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता की ओर से झलकारी बाई को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने समाज को ऐसी महान वीरांगना की कथा से प्रेरित करने के लिए घोषणा करते हुए कहा कि पलवल के आगरा चौक पर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम झलकारी बाई के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पलवल के मोहन नगर के वार्ड नंबर-4 में कोली समाज के एक भव्य भवन का निर्माण किये जाने की भी घोषणा की। इस भवन में झलकारी बाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जिससे भावी पीढ़ी को इनकी गाथाओं से अवगत करवाया जा सकेगा। इस पर लगभग तीन करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।

मनोहर लाल ने कहा कि यह दिन बहुत ही गौरव का दिन है, जब वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सन् 1857 में स्वाधीनता संग्राम में हम सभी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना है, लेकिन वीरांगना झलकारी बाई के नाम को इतिहास में उतना अधिक नहीं जानते। वीरांगना झलकारी बाई झांसी की रानी की हमशक्ल थी और वे महिला सेना की सेनापति थी, जिन्होंने अपने शौर्य से झांसी की रानी की जान बचाने और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी।

झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर, 1830 में हुआ था। उन्होंने कहा कि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में झलकारी बाई जी का वर्णन किया है कि- आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सीखा गई, रानी बन जौहर दिखा गयी, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। उन्होंने कहा कि हमारे समाज की महिलाएं, बेटियां झलकारी बाई से प्रेरणा लें यही हमारा लक्ष्य है। आज के युग में हमारी बेटियां अंतरिक्ष, खेल, डिफेंस सहित विभिन्न क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं।

आत्मनिर्भरता से होगा गरीबी का स्थाई उन्मूलन

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी एक रपट में कहा गया है कि भारत में वर्ष 2015-16 में जो गरीबी 25 प्रतिशत थी वह वर्ष 2021 के दौरान घटकर 15 प्रतिशत रह गई है। साथ में यह भी कहा है कि आय में असमानता बढ़ी है। रपट के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में करीब 37 हजार रुपए थी वह वर्ष 2022 में बढ़कर करीब दो लाख रुपए हो गई है।

भारत सरकार देश की करीब 80 करोड़ आबादी को हर माह मुफ्त अनाज दे रही है। यह देश की कुल आबादी का करीब 57 प्रतिशत होता है। निशुल्क खाद्य वितरण योजना के तहत यह सुविधा आगामी पांच वर्ष तक जारी रहेगी।

बतादें भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दस सितंबर 2013 को अधिसूचित हुआ था। इसका उद्देश्य नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सहज मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण पांच किलो अनाज उपलब्ध कराना है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को चावल तीन रुपए प्रति किलो, गेहूं दो रुपए तथा मोटा अनाज एक रुपए प्रति किलो अनाज दिया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन दिया गया था। वर्ष 2028 तक एक बार फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की दो तिहाई आबादी को लगभग मुफ्त अनाज दिया जाएगा। वैश्विक संगठनों ने भारत की इस योजना की खुलकर प्रशंसा की है। दुनिया के अर्थ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के समय इस योजना से देश की बड़ी आबादी को गरीबी के दलदल से बचाने का काम किया था।

देश में लागू की गई सामुदायिक रसोई, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गरीबी के स्तर को कम करने का काम किया है। हालांकि इन योजनाओं के कारगर ढंग से लागू करने में अभी सुधार की गुंजाइश है।

केंद्र सरकार का खाद्य सबसिडी खर्च वर्तमान आकलन के मुताबिक दो लाख करोड़ रुपए है। यह आगामी समय में बढ़ेगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय खाद्य निगम को इस समय गेहूं पर 27 रुपए तथा चावल पर 39 रुपए प्रति किलोग्रामी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।

रपट के अनुसार पिछले पांच वर्ष में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इन योजनाओं के चलते लाभार्थियों को भी ध्यान देना होगा कि असल जरुरतमंदों तक लाभा पहुंचे ताकि केंद्र सरकार पर सबसिडी का बोझ कम हो। लाभार्थियों को चाहिए कि वे केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार संबंधी योजनाओं का फायदा उठाते हुए आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। मुफ्त की सेवाएं आदमी को आलसी बना देती हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करना न केवल अपनी बल्कि राष्ट्र की सेहत के लिए भी फायदेमंद रहेगा।

– विशेष प्रतिनिधि

चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु सेंटर फॉर कंपीटिटिव एग्जामिनेशन खोला है। सेंटर में उन विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी।

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी के क्षेत्र ब्राह्मण माजरा में 21 एकड़ भूमि पर बनने वाले डेयरी काम्प्लेक्स में ग्वालों को एक ही स्थान पर अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

पैरा एशियाई खेलों में हरियाणवियों का धाकड़ प्रदर्शन

संगीता शर्मा

चीन के हांगझोऊ में 22 से 28 अक्तूबर तक आयोजित एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा-एथलीटों ने भारत के अब तक के सबसे अधिक पदकों के साथ इतिहास रच दिया है। भारतीय पैरा एथलीटों ने हांगझोऊ एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए 107 पदकों के रिकॉर्ड से चार पदक अधिक जीते। उन्होंने 29 स्वर्ण पदकों सहित कुल 111 पदक जीते। इससे पहले भारत ने एशियाई पैरा खेलों के 2010 संस्करण में 14 पदक, 2014 में 33 और 2018 में 72 पदक जीते थे। इन खेलों की शुरुआत के बाद से यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जहां भारत समग्र पदक तालिका में पांचवें स्थान पर रहा। हरियाणा के पैरा खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी शानदार रहा। खेल विभाग, हरियाणा के अनुसार पैरा एशियन गेम्स 2022 में हरियाणा के पैरा खिलाड़ियों 8 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 17 कांस्य पदक को मिलाकर 30 खिलाड़ियों ने 34 पदक एथलेटिक्स एवं अन्य खेल / इवेंट में प्राप्त किए।

गौरतलब है कि भारत ने इस वर्ष अपना सबसे बड़ा दल भेजा था, जिसमें 303 एथलीट (191 पुरुष और 112 महिला) शामिल थे। कुल 111 पदकों में से महिला एथलीटों ने 40 पदकों का योगदान दिया है, यानी कुल पदकों में 36 प्रतिशत की हिस्सेदारी की। पैरा एथलीटों ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ कुल 111 पदक जीते।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस प्रतियोगिता में देश के लिए पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह प्रदर्शन हमारे एथलीटों की कड़ी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों से जुड़ी सही नीतियों की शुरुआत को दर्शाता है। चाहे वह ज़मीनी स्तर पर खेलो इंडिया योजना हो या सर्वोत्कृष्ट एथलीटों से संबंधित टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, इन योजनाओं के माध्यम से दिया गया समर्थन वास्तव में अब परिणाम देने लगा है।

सागों का सरदार है बथुआ

भारतीय संस्कृति में अनादि काल से बथुए का साग और रायता बनता रहा है। कहा जाता है, विश्व की सबसे पुरानी महल बनाने की कला पुस्तक 'शिल्प शास्त्र' में लिखा है कि हमारे बुजुर्ग अपने घरों को हरा रंग करने के लिए मिट्टी के पलस्तर में बथुआ मिलाते थे। इतना ही नहीं सिर से डैंडर्फ साफ करने के लिए भी इसी बथुए के पानी से सिर धोया जाता था।

सर्दी के मौसम में चिकित्सक भी इसके सेवन की सलाह देते हैं। बथुआ विटामिनों से भरपूर है। इसमें कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, मैगनीज, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम व जिंक आदि मिनरल्स होते हैं।100 ग्राम कच्चे बथुवे यानि पत्तों में 7.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4.2 ग्राम प्रोटीन व 4 ग्राम पोषक रेशे होते हैं।

जब बथुआ मट्ठा, लस्सी या दही में मिला दिया जाता है तो यह किसी भी मांसाहार से ज्यादा प्रोटीन वाला व किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से ज्यादा सुपाच्य व पौष्टिक आहार बन जाता है। साथ में बाजरे या मक्का की रोटी, मक्खन व गुड़ की डली हो तो इसे खाने के लिए देवता भी तरसते हैं।

चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिला को खासतौर पर विटामिन बी, सी व आयरन की गोली सेवन के लिए बताई जाती है। बथुए में ये सब गुण हैं। कहने का तात्पर्य है कि बथुआ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए अमृत समान है।

बथुआ का साग प्रतिदिन खाने से गुर्दों में पथरी नहीं होती। बथुआ अमाशय को बलवान बनाता है, गर्मी से बढ़े हुए यकृत को ठीक करता है। बथुए के साग का सही मात्रा में सेवन किया जाए तो निरोग रहने के लिए सबसे उत्तम औषधि है।

आयुर्वेद के मुताबिक बथुए का सेवन कम से कम मसाले डालकर करें। नमक न मिलाएं तो अच्छा है,यदि स्वाद के लिए मिलाना पड़े तो काला नमक मिलाएं और देशी गाय के घी से छौंक लगाएं। बथुए का उबला हुआ पानी अच्छा होता है तथा दही में बनाया हुआ रायता स्वादिष्ट होता है।

बथुए में जिंक होता है जो कि शु वर्धक होता है। बथुआ कब्ज दूर करता है। अगर पेट साफ रहेगा तो कोई भी बीमारी शरीर में लगेगी ही नहीं, ताकत और स्फूर्ति बनी रहेगी। कहने का मतलब है कि जब तक इस मौसम में बथुये का साग मिलता रहे नित्य इसकी सब्जी खाएं।

आप ने अपने दादा-दादी से ये कहते जरूर सुना होगा कि हमने तो सारी उम्र अंग्रेजी दवा की एक गोली भी नहीं ली उनके स्वास्थ्य व ताकत का राज शायद यही बथुआ है।

-साभार

होडल में खुलेगा गौ सेवा अस्पताल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोपाष्टमी के पावन अवसर पर जिला पलवल के होडल क्षेत्र में स्थित गौ सेवा धाम परिसर में गौ पूजन किया और बहुमंजिला गौ सेवा अस्पताल की आधारशिला रखी। उन्होंने प्रदेश के हर नागरिक की खुशहाली, स्वस्थ्य व सुखद जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री ने गोपाष्टमी पर्व की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर जीव के प्रति सेवा भाव का दिन है, ऐसे में गौ सेवा से जुड़ी संस्थाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा दान देना चाहिए। हमें गौधन को बचाने के लिए उसकी उपयोगिता को बढ़ाना होगा।

मुख्यमंत्री ने खुशी जताई कि उन्हें गौ सेवा धाम आने का अवसर मिला, ऐसे में वे अपने आप को धन्य समझते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अस्पताल और मानव सेवा तो हम सबके मन मे आती है लेकिन पशुओं, जीव जंतुओं और पक्षियों की सेवा का भाव बिरले लोगों के मन में ही आता है। उन्होंने गौ सेवा धाम के संचालन के लिए देवी चित्रलेखा की सरहाना की और अपने कोष से 21 लाख रुपए सेवा धाम को देने की घोषणा की।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए देश और प्रदेश की सरकार कृत संकल्प है। साथ ही गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार और गौसेवा आयोग प्रभावी रूप से काम कर रहा है। सरकार द्वारा गौ सेवा आयोग के बजट में 10 गुणा बढ़ोतरी करते हुए मौजूदा बजट 400 करोड़ रुपए कर दिया है।

हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की ओर से पंचकूला में 'मिशन हरियाणा कर्मयोगी' मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण शिविर शुरू किया। ये ट्रेनर बाद में जिलों में लगभग 3.3 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सभी उपायुक्तों को शिकायत समिति की बैठकों में शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक कार्यवाही रिपोर्ट 24 घंटों के भीतर जारी करना अनिवार्य है।

क्राफ्ट व लोक संस्कृति का अनूठा संगम

सूरजकुंड के दिवाली उत्सव में छाया रहा वोकल फॉर लोकल

संगीता शर्मा

तीज-त्यौहार के उत्सव महिलाओं के बिना अधूरे हैं। महिलाएं समाज की अहम कड़ी हैं और हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्त व समृद्ध करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' व आत्मनिर्भर भारत को मूर्त रूप देने के लिए फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला परिसर में प्रथम दिवाली उत्सव -2023 का आयोजन 3 नवंबर से 10 नवंबर तक किया गया। मेले में जहां बच्चों के लिए रचनात्मक क्रियाशीलता को बढ़ावा देती हुई अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी पर्यटकों ने भरपूर आनंद उठाया। दिवाली उत्सव में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने कला का प्रदर्शन किया और सैलानियों ने जमकर खरीददारी की। समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धनतेरस, छोटी दीपावली, दिपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सूरजकुंड में पहली बार दिवाली मेला आयोजित किया गया। इसी प्रकार, एक मेला आज से शुरू होकर 22 जनवरी, 2024 तक भगवान श्रीराम की जन्म भूमि अयोध्या में भी आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भगवान श्रीराम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे।

महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं

मनोहर लाल ने कहा कि इससे पहले भी हरियाली तीज उत्सव पर राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 50 हजार महिलाओं को मेरी ओर से एक भाई स्वरूप कोथलियां दी गई थी। इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं को एक दीपक, कैलेंडर और अन्य वस्तुएं भेंट स्वरूप दी गई। मनोहर लाल ने कहा कि विगत 9 वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई हैं, जिसे धरातल तक पहुंचाकर सभी को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सम्मानित भी किया।

सूरजकुंड में प्रथम दिवाली उत्सव में असंख्य स्टालें लगाई गई, जिनके माध्यम से लघु उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितैषी नीतियों का अनुसरण करते हुए देश के कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं को मेला में बिक्री के लिए रखा गया था। वोकल फार लोकल की नीति का प्रदेश में 70 हजार लघु उद्योगों को यहां बढ़ावा दिया गया है, इनमें स्वयं सहायता समूहों की पांच हजार महिलाएं भी अपनी आय बढाकर आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हैं।

उत्सव के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश के पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि आज हमारे पास पैसा है, बड़ा मकान है लेकिन खुशी नहीं है। ऐसे में हमें अपने हैपीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए मेला संस्कृति को पुनः जिंदा करना होगा। बुजुर्गों की बनाई मेला संस्कृति की परंपरा को सरकारी तौर पर भी प्रोत्साहन देना होगा।

महिला सशक्तिकरण की झलक

आधुनिक जमाने में अब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं तथा समानता का प्रतीक बनकर उभर रहीं हैं। ऐसा ही नज़ारा दिवाली उत्सव के दौरान देखने को मिला। 62 वर्षीय दीपा बंसल ने दिवाली से संबंधित सजावट सामग्री जैसे झालर, दीये, लटकन का स्टाल लगाया। उनके द्वारा लगाई गयी स्टाल नंबर एफसी-10 पर दिवाली के त्यौहार के लिए सजावट के सामान की खरीददारी के लिए लोगों की ख़ासा भीड़ लगी रही।

अचार, मुरब्बे व सिरके

दिवाली उत्सव में श्री कृष्णा पिकल्स स्टॉल पर स्टॉल के मालिक जितेंद्र ने अपनी माता कृष्णा यादव के बारे में बताया कि कैसे शिक्षा से वंचित रहने के बावजूद भी कृष्णा यादव ने कामयाबी का सफर तय किया है। दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाली कृष्णा यादव एक छोटे से कमरे में अचार बनाना का काम शुरू किया था और अब वे अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। कृष्णा यादव श्री कृष्णा पिकल्स की मालकिन हैं और आज चार लघु इकाइयां चला रही हैं, जिनमें अचार से जुड़े 152 उत्पाद तैयार किए जाते हैं।

खुशबू वाले दीयों से जगमगाए अपना घर

फरीदाबाद निवासी विवेक तलवार ने टी लाइट कैंडल बनाने के स्टार्ट अप की शुरुआत की। बताया कि दीये व टी लाइट कैंडल पूरी तरह से उनके द्वारा ही बनाये गए। छोटे स्तर पर ही सही पर मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में वह भी अपना योगदान दे रहे हैं। स्टाल पर दिवाली के त्यौहार पर घरों को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के दीये प्रदर्शित किए।

कलाकारों ने मचाया धमाल

बड़ी चौपाल पर हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव वी उमाशंकर व सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के महानिदेशक अमित कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देश अनुसार कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के संगीत अधिकारी डॉ दीपिका और नृत्य अधिकारी सुमन ढांगी द्वारा सभी जिलों के अच्छे कलाकारों द्वारा हरियाणवी संस्कृति की झलक नृत्य के माध्यम द्वारा प्रस्तुत की गयी। हरियाणा के त्यौहारों की शुरुआत तीज से होकर होली पर समाप्त होती है। इसी के बीच के मुख्य त्योहारों की झलकियां सारंगी वादन, बीन वादन, डेरू, चिमटा, हरियाणा के पारंपरिक लोक वाद्ययंत्र धमाल, तीज डांस, खोड़िया नृत्य पनिहारी नृत्य व विवाह के गीत इन सभी को मिक्स करके ग्राउंड फिनाले डांस तथा रसिया नृत्य प्रस्तुत कर बड़ी चौपाल पर बैठे सभी दर्शकों को मोहित कर तालियां बजाने पर मज़बूर कर दिया।

हरियाणवी वेशभूषा एवं संस्कृति की झलकियां प्रस्तुत करते हुए राम चंद्र रोहिला एंड पार्टी जींद ने बेहतरीन हरियाणवी लोक गीत व रागनी बड़ी चौपाल पर प्रस्तुत कर हरियाणवी रंग जमाया। इसके बाद बॉलीवुड गायिका भूमिका यादव ने बड़ी चौपाल पर अपनी प्रस्तुति दी। अंकुर शरण द्वारा हर वर्ग के कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए जुगलबंदी कार्यक्रम में विभिन्न गीतों की धुन को प्रस्तुत किया।

हरियाणवी लोकनृत्यों, स्वागत करता दलों व सुरमयी शाम, मेरी आवाज मेरी पहचान के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। सुरमयी शाम के कार्यक्रमों में संगीत निर्देशन का कार्य वेवल कुमार द्वारा किया गया तथा इस सारे कार्यक्रम का नेतृत्व कला एवं सांस्कृतिक अधिकारी, (संगीत), नृत्य, चित्रकला, थियेटर, मूर्तिकला) के साथ मिलकर विभाग के सभी कर्मचारियों के सहयोग से किया गया।

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com